मादक पदार्थ नियंत्रण: विज़न दस्तावेज़ 2026-2029

आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक मुद्दे | समाचार संदर्भ: NCORD की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक और मादक पदार्थ नियंत्रण पर विज़न दस्तावेज़ 2026-2029, 26 जून 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

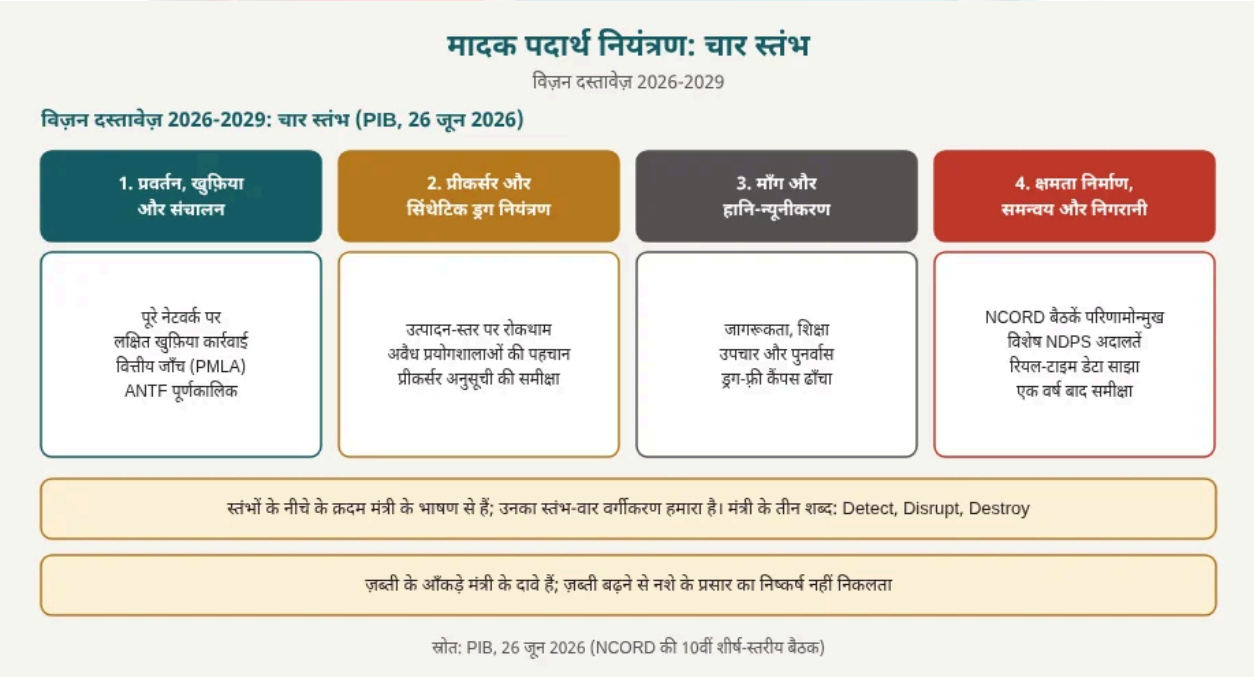
भारत में मादक पदार्थों से निपटने का क़ानूनी ढाँचा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज़ (NDPS) अधिनियम, 1985 है और केंद्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) समन्वय करता है। नारको-समन्वय केंद्र (NCORD) केंद्र, राज्यों और एजेंसियों के बीच समन्वय का मंच है, जिसकी बैठकें शीर्ष, राज्य और ज़िला स्तर पर होती हैं। इस विषय में आँकड़े और दावे आसानी से भ्रम पैदा करते हैं, इसलिए यह लेख आँकड़ों के साथ उनकी सीमाएँ भी बताता है।

खबरों में क्यों

PIB के अनुसार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 26 जून 2026 को नई दिल्ली में NCORD की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, “मादक पदार्थ नियंत्रण पर विज़न दस्तावेज़ (2026-2029)” और “NCB वार्षिक रिपोर्ट-2025” जारी की, जम्मू और गुवाहाटी में NCB के क्षेत्रीय कार्यालयों का ई-उद्घाटन किया और 2,09,500 किलो नशीले पदार्थों के नष्ट करने के लिए “ऑनलाइन ड्रग्स डिस्पोज़ल पखवाड़ा” शुरू किया।

मुख्य अवधारणा: चार स्तंभ और “पहचानो, बाधित करो, नष्ट करो”

PIB के अनुसार रोडमैप चार स्तंभों पर है: प्रवर्तन, खुफ़िया और संचालन; पूर्ववर्ती रसायन (प्रीकर्सर) और सिंथेटिक ड्रग नियंत्रण; माँग और हानि-न्यूनीकरण; और क्षमता निर्माण, समन्वय और निगरानी। गृह मंत्री ने इसे तीन शब्दों में रखा: पहचानो (Detect), बाधित करो (Disrupt), नष्ट करो (Destroy)। साथ ही “तस्करों के प्रति कठोर, पीड़ितों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण” रुख़ बताया गया। हर उप-स्तंभ के लिए लक्ष्य और समय-सीमा तय होने की बात कही गई है।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

अवसर	**NCORD की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक, नई दिल्ली, 26 जून 2026। PIB के अनुसार अब तक 15,876 ज़िला-स्तरीय, 266 राज्य-स्तरीय और 7 कार्यकारी समिति की बैठकें हुई हैं।**
जारी दस्तावेज़	मादक पदार्थ नियंत्रण पर विज़न दस्तावेज़ (2026-2029); NCB वार्षिक रिपोर्ट-2025; जम्मू और गुवाहाटी में NCB के क्षेत्रीय कार्यालय।
निपटान पखवाड़ा	2,09,500 किलो नशीले पदार्थों के नष्ट करने का लक्ष्य, मूल्य 6,000 करोड़ रुपये (PIB)। गृह मंत्री ने "एक दिन में 6,000 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ नष्ट करने" को उपलब्धि बताया।
राज्यों को निर्देश (मंत्री के भाषण के अनुसार)	प्रमुख NDPS मामलों में वित्तीय जाँच अनिवार्य; पुलिस प्रमुखों से निजी रुचि लेने की अपेक्षा; ANTF को पूर्णकालिक इकाइयों में बदलना; विशेष लोक अभियोजक; उच्च न्यायालयों से विशेष NDPS अदालतें; हर विभाग में नोडल अधिकारी; स्कूलों और उच्च शिक्षा में "ड्रग-फ़्री कैंपस" ढाँचा; रियल-टाइम डेटा साझा करना।
केंद्रीय मंत्रालयों से अपेक्षाएँ	पूर्ववर्ती रसायनों और साइकोट्रॉपिक पदार्थों की अनुसूची की समीक्षा; स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दवा के दुरुपयोग और ऑनलाइन फ़ार्मेसी की निगरानी; सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान, उपचार और पुनर्वास का विस्तार।
निगरानी	गृह मंत्री के अनुसार योजना की एक वर्ष बाद समीक्षा होगी और आवश्यकता होने पर उसे फिर से परिभाषित किया जाएगा।
मंत्री द्वारा दिए गए आँकड़े (PIB में उद्धृत)	ज़ब्ती: 2004-2014 में 40,000 करोड़ रुपये (26 लाख किलो); 2014-2026 में 1,84,000 करोड़ रुपये (1 करोड़ 18 लाख किलो)। नष्ट: 8,000 करोड़ रुपये बनाम 89,896 करोड़ रुपये। अवैध अफ़ीम की खेती नष्ट: 2020 में 10,000 एकड़, 2025 में 42,282 एकड़। मामले और गिरफ़्तारियाँ: 1,73,000 और 1,95,000 बनाम 8,75,000 और 10,97,000।

आँकड़ों को कैसे पढ़ें

अवधियों की लंबाई: तुलना 2004-2014 (दस वर्ष) और 2014-2026 (बारह वर्ष) की है। हमारी गणना: ज़ब्त मात्रा औसतन लगभग 2.6 लाख किलो प्रति वर्ष से लगभग 9.8 लाख किलो प्रति वर्ष। फिर भी सारा अंतर अवधि की लंबाई का नहीं, और PIB यह नहीं बताता कि 2026 के आँकड़े पूरे वर्ष के हैं या जून तक के।

ज़ब्ती का अर्थ: ज़ब्ती बढ़ने का अर्थ प्रवर्तन का बढ़ना भी हो सकता है और आपूर्ति का बढ़ना भी। इसलिए ज़ब्ती से नशे के प्रसार में कमी या वृद्धि का सीधा निष्कर्ष नहीं निकलता। PIB का पाठ भी इसे प्रवर्तन की सफलता के रूप में प्रस्तुत करता है; हमारे पास उपयोग के प्रसार का कोई आँकड़ा इस पाठ में नहीं है।

ज़ब्त और नष्ट का फ़र्क़: PIB में ज़ब्त और नष्ट किए गए पदार्थों के आँकड़े अलग-अलग दिए गए हैं। दोनों के बीच का समय-अंतर और नष्ट करने की प्रक्रिया PIB में नहीं बताई गई, इसलिए दोनों को एक-दूसरे का सीधा अनुपात न मानें।

यह विषय क्यों मायने रखता है

संघीय समन्वय: क़ानून-व्यवस्था राज्य सूची में है, जबकि NDPS अधिनियम संसदीय क़ानून है। इसलिए योजना की सफलता राज्यों की पुलिस, ANTF और अदालतों पर निर्भर है। मंत्री के निर्देश राज्यों से अपेक्षाएँ हैं; PIB यह नहीं बताता कि राज्यों ने इन्हें माना है। यह हमारा पाठ है।

सुरक्षा और स्वास्थ्य का मिश्रण: गृह मंत्री ने मुद्दे को "केवल क़ानून-व्यवस्था या जन-स्वास्थ्य का नहीं" बताया और आंतरिक सुरक्षा, नार्को-आतंक वित्तपोषण और युवाओं से जोड़ा। PIB में माँग और हानि-न्यूनीकरण एक अलग स्तंभ है; उसके ठोस लक्ष्य PIB में नहीं हैं।

बहस के बिंदु और सावधानियाँ

घोषणा बनाम क्रियान्वयन: हमने PIB का पूरा पाठ पढ़ा। विज़न दस्तावेज़ का अपना पाठ और उसके उप-स्तंभों के लक्ष्य हमने नहीं पढ़े, इसलिए हम उन लक्ष्यों के बारे में कुछ नहीं कहते। निपटान पखवाड़े के परिणाम की आधिकारिक जानकारी हमने नहीं पढ़ी; जुलाई 2026 में संसद के उत्तरों पर आधारित PIB के नोट उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हमने नहीं किया।

मंत्री के भाषण का स्वर: PIB पाठ का बड़ा हिस्सा मंत्री के भाषण का सार है। आँकड़े और विशेषण (जैसे "निर्मम दृष्टिकोण") मंत्री के शब्द हैं और हमने उन्हें स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया।

स्रोत और सीमाएँ: पढ़ा गया स्रोत: PIB विज्ञप्ति (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2278233&lang=1&reg=3), पूरी। NCB वार्षिक रिपोर्ट-2025 और विज़न दस्तावेज़ हमने नहीं खोले।

पूर्व लेख से अंतर: pcsmantra.com पर "नशा मुक्त युवा अभियान" पर एक अलग लेख है; यह लेख NCORD और विज़न दस्तावेज़ पर है और उसकी नक़ल नहीं है। इस विज़न दस्तावेज़ या NCORD पर हमें कोई लेख नहीं मिला (खोज: "NCORD", "नारको", "मादक पदार्थ")।

आगे की राह

इस लेख को 26 जून 2026 के PIB पाठ की स्थिति के रूप में पढ़ें। विज़न दस्तावेज़ के लक्ष्यों और उनकी वार्षिक समीक्षा पर आधिकारिक जानकारी आने पर निष्कर्ष बदल सकते हैं।

अवधारणा में अंतर

चार बातें अलग रखें: (1) PIB के अनुसार जारी दस्तावेज़ और लक्ष्य; (2) मंत्री के दिए आँकड़े और दावे; (3) राज्यों से अपेक्षाएँ बनाम उनका पालन; और (4) हमारी व्याख्याएँ और गणनाएँ।

मेंस दृष्टि

GS-III: आंतरिक सुरक्षा, संगठित अपराध और आतंकवाद से उसका संबंध; GS-II: केंद्र-राज्य संबंध, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय। उत्तर में ज़ब्ती के आँकड़ों की सीमाएँ ज़रूर लिखें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

मादक पदार्थ नियंत्रण पर विज़न दस्तावेज़ (2026-2029) के चार स्तंभों की समीक्षा कीजिए और बताइए कि सफलता किन शर्तों पर निर्भर है।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: NDPS ढाँचा और NCORD।

मुख्य भाग में: चार स्तंभ; राज्यों की भूमिका; ज़ब्ती के आँकड़ों की सीमाएँ; माँग-घटाने की चुनौती।

निष्कर्ष में: प्रवर्तन और समन्वय को माँग तथा हानि-न्यूनीकरण से जोड़ें; ज़ब्ती या नष्ट किए गए पदार्थों की मात्रा को नशे का प्रसार घटने का सीधा प्रमाण न मानते हुए राज्यों के क्रियान्वयन और परिणामों से सफलता परखें।

स्रोत

- PIB, NCORD की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक और विज़न दस्तावेज़ (26 जून 2026)

विज़न दस्तावेज़, NCB वार्षिक रिपोर्ट-2025 और निपटान पखवाड़े के परिणाम नहीं पढ़े गए।

याद रखें: PIB के अनुसार 26 जून 2026 को जारी विज़न दस्तावेज़ (2026-2029) चार स्तंभों पर है और राज्यों से कई ठोस क़दमों की अपेक्षा रखता है। ज़ब्ती के आँकड़े मंत्री के दावे हैं; उनसे नशे के प्रसार का निष्कर्ष नहीं निकलता और दस्तावेज़ के लक्ष्य हमने नहीं पढ़े।